भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1286

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

.....

अटल भूजल योजना के उद्देश्य

1286. श्री सुनील कुमार सोनीः

श्री मोहन मंडावीः

श्री विजय बघेलः

श्री अरुण सावः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल भूजल योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) हर घर नल से जल कार्यक्रम के अंतर्गत अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेंडर-मरवाही सहित छत्तीसगढ़ में उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): अटल भूजल योजना को व्यवहार परिवर्तन और उपयुक्त जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ क्षमता निर्माण और मांग पक्ष प्रबंधन को लक्षित करने वाली गतिविधियों पर जोर देने के साथ समुदाय के माध्यम से स्थायी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्र स्तरीय गतिविधियों के अभिसरण के माध्यम से भागीदारीपूर्ण भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना भी है।

यह योजना 01.04.2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 7 राज्यों, अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।

(ग): छत्तीसगढ़ अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को संस्थागत तैयारी, भूजल के अति-दोहन/जल तनाव की स्थितियों के अलावा हाइड्रोजियोलॉजिकल स्थितियों सहित कई मानदंडों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था।

(घ): 7 राज्यों में चिह्नित किए गए सभी 8220 ग्राम पंचायतों में समुदायों को मौजूदा ग्राम और जल स्वच्छता समितियों के माध्यम से संगठित किया गया है और भूजल डेटा संग्रह और सूचित और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के लिए जल बजटिंग के महत्व के संदर्भ में केंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी क्षमताओं का निर्माण किया गया है।

सभी सहभागी ग्राम पंचायतों में समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजनाएँ (डब्ल्यूएसपी) तैयार की गई हैं। इन डब्ल्यूएसपी में जल बजट और प्रस्तावित आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप जैसे चेक बांध, फार्म तालाब, रिचार्ज शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाएं और सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि जैसे मांग पक्ष के हस्तक्षेप के बारे में विवरण शामिल हैं। इन हस्तक्षेपों को संबंधित लाइन विभागों द्वारा विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल लागू कर रही है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 24.07.2023 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 9.40 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.07.2023 तक, देश के 19.47 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 12.63 करोड़ (64.9%) घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 6.84 करोड़ को 2024 तक कवर किए जाने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन की राज्य-वार स्थिति सार्वजनिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड:

https://ejalpower.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर उपलब्ध है।

पूरे देश में जेजेएम के लक्ष्य को गति और पैमाने के साथ प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कई कदमों के माध्यम से मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्यों का समर्थन कर रही है, जिसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की संयुक्त चर्चा और अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि शामिल हैं। जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जेजेएम के कार्यान्वयन हेतु एक विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश; ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशानिर्देश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किए गए हैं।

(ङ): चूंकि, अटल भूजल योजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है, इसलिए इस योजना के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

जल जीवन मिशन के तहत जिलेवार धन आवंटन, योजनाएं/परियोजनाएं और विवरण न ही बनाए जाते हैं और न ही अनुरक्षित होते हैं । हालाँकि, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और निधि उपयोग का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

राशि (करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
	प्रारंभिक जमा	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोगिता	
2019-20	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	37.55
2020-21	58.17	445.52	334.14	392.31	223.80	221.10
2021-22	168.52	1,908.96	477.24	645.76	498.69	488.63
2022-23	147.06	2,223.98	2,223.98	2,371.04	2,097.06	2,079.48
2023-24*	273.99	4,485.60	496.39	770.38	203.29	202.26

* 24.07.2023 तक स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****